एलपीजी की उपलब्धता पर्याप्त है, आमजन को परेशानी नहीं होगी- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने एलपीजी सप्लाई की समीक्षा की तथा खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग कर्मियों के अवकाश निरस्त किए

जयपुर, 11 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारु तथा सामान्य है। इसकी आपूर्ति को लेकर प्रदेश में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है।

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला कलेक्टरों व संबंधित अधिकारियों को निरन्तर मॉनिटरिंग के निर्देश दिये ताकि आम उपभोक्ता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और एलपीजी गैस व पैट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी और कालाबाजारी नहीं हो पाये।

शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में निर्देश दिए एलपीजी गैस आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए राज्य एवं जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाए। उन्होंने नागरिक आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्मिकों के अवकाश निरस्त किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए एलपीजी गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी या कालाबाजारी पर विशेष निगरानी रखी जाए। ऐसे मामले के पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारी निरीक्षण कर निरंतर मॉनिटरिंग करें।

शर्मा ने कहा कि ऐसे समय में अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शैक्षिणक संस्थानों, अस्पतालों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुडे संस्थानों में गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित रखी जाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में अधिकारियों को एलपीजी गैस आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए।

भारत ने रूस से 3 करोड़ बैरल क्रूड ऑइल खरीदा

नई दिल्ली, 11 मार्च। मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। विशेष रूप से होरमुज जलडमरूमध्य के बंद होने जैसी स्थिति ने कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर दबाव बढ़ा दिया है। यही कारण है कि भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से वैकल्पिक स्त्रोतों की ओर रुख किया है।

जानकारी के अनुसार, भारत की रिफाइनरियों ने रूस से लगभग 30 मिलियन यानी करीब 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल की खरीद की है।

यह खरीद ऐसे समय पर हुई है, जब अमेरिका ने भारत को इस संबंध में अस्थायी छूट प्रदान की है, ताकि वह पश्चिम एशिया से कम हुई आपूर्ति की भरपाई कर सके।

पिछले साल भारत ने अमेरिका के दबाव के चलते रूस से तेल खरीद में कमी करना शुरू कर दिया था। उस समय भारत ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सऊदी अरब और इराक जैसे देशों से तेल आयात बढ़ाया था।

राजस्थान दिवस का मुख्य समारोह 19 मार्च को जालोर में होगा

मुख्यमंत्री भजनलाल 15 को जयपुर में ''विकसित राजस्थान रन'' का फ्लैग ऑफ करेंगे

जयपुर, 11 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर गत वर्ष से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर राजस्थान दिवस मनाने की शुरूआत की गई। इसी क्रम में इस बार भी राज्य सरकार प्रदेशभर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा (19 मार्च) को राजस्थान दिवस मनाने जा रही है। प्रदेशभर में 14 मार्च से विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत की जाएगी, जो 19 मार्च तक आयोजित होंगे।

■ राजस्थान दिवस समारोह के तहत 16 मार्च को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में ''राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस'' का आयोजन होगा तथा 17 मार्च को जयपुर में ''राजस्थान युवा शक्ति दिवस'' आयोजित होगा।

आयोजन की शुरुआत 14 मार्च से सात दिवसीय स्वच्छता सप्ताह के साथ होगी। 15 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय 'विकसित राजस्थान रन' का आयोजन होगा जिसका फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे।

15 मार्च को ही 'राजस्थान को जानें' डिजिटल क्विज का शुभारंभ तथा जयपुर में ओडीओपी मेला एवं प्रदर्शनी का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया जाएगा। इसी दिन शाम को दिल्ली के बीकानेर हाउस में पांच दिवसीय 'राजस्थान दिवस/बीकानेर हाऊस' का शुभारंभ किया जाएगा।

16 मार्च को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में 'राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस' का आयोजन किया जाएगा। 17 मार्च को जयपुर में 'राजस्थान युवा शक्ति दिवस' मनाते हुए राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन होगा। 18 मार्च को किसान एवं पशुपालक समृद्धि दिवस मनाया जाएगा। शाम को प्रदेशभर में राजकीय मंदिरों में आरती का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री भी महाआरती में शामिल होंगे।

राजस्थान दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन 19 मार्च को जालोर में किया जाएगा। इस दौरान लाभार्थी सम्मेलन आयोजित होगा। शाम को जयपुर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

प्रतियोगी परीक्षा के हाईटैक नकल गिरोह का सदस्य गिरफ्तार

जयपुर, 11 मार्च। स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप राजस्थान (एसओजी) ने प्रतियोगी परीक्षाओं में हाईटेक तरीके से नकल कराने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर डमी कैंडिडेट के माध्यम से परीक्षा दिलाने और स्मार्ट डिवाइस के जरिए प्रश्नपत्र हल करवाने में सहयोग करने का आरोप है।

■ एसओजी, गिरोह के अन्य सदस्यों व उपभोग में लाई गई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कर रही है।

एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 21 मई 2023 को आयोजित सहायक अभियंता सिविल (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 की जांच के दौरान सामने आया कि मूल अभ्यर्थी इंदराज सिंह की जगह किसी अन्य व्यक्ति ने डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी। प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ कर दूसरे व्यक्ति की फोटो लगाकर षड्यंत्रपूर्वक परीक्षा दिलाई गई थी।

जांच में पहले मूल अभ्यर्थी इंदराज सिंह, सहयोगी आरोपी परमेश्वर लाल और सलमान खान को गिरफ्तार कर चालान पेश किया जा चुका है। वहीं डमी परीक्षार्थी गुरदीप दास निवासी हिसार (हरियाणा) को 27 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।

जांच में सामने आया कि गुरदीप दास परीक्षा केन्द्र में विशेष स्मार्ट डिवाइस लेकर प्रवेश करता था और प्रश्नपत्र की फोटो लेकर बाहर भेज देता था। बाहर मौजूद अजीत कुमार इंटरनेट और अन्य विशेषज्ञों की मदद से प्रश्न हल कर वापस भेजता था, जिससे डमी परीक्षार्थी परीक्षा में सफल हो जाता था।

मामले की जांच एसओजी के उपमहानिरीक्षक परिस देशमुख के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह द्वारा की जा रही है। एसओजी गिरोह के अन्य सदस्यों और उपयोग में लाई गई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के संबंध में भी जांच कर रही है।

इस पूरे प्रकरण में अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें 1 मूल अभ्यर्थी, 1 डमी परीक्षार्थी, 2 मध्यस्थ और 1 सहयोगी शामिल है।

'अब जवाबी कार्यवाही नहीं लगातार हमले होंगे'

तेहरान/बेरूत, 11 मार्च। पश्चिम एशिया में 12 दिनों से जारी सैन्य संघर्ष के बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि अब वह केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के खिलाफ लगातार हमले करेगा। इस कारण वैश्विक तेल बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है और तेल की कीमतें 200 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। ईरान ने मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी और इजराइली बैंकों के साथ-साथ कई अमेरिकी टेक कंपनियां को भी निशाना बनाने की बात कही है। लेबनान के लेबनानी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल (एलबीसीआई) और ईरान की स्थानीय समाचार एजेंसी ने ईरान की राजधानी तेहरान स्थित खातम अल-अनबिया सैन्य कमान मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फ़कारी ने बुधवार को यह घोषणा की।

इंटरनैशनल एनर्जी एजेंसी 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में उतारेगी

नई दिल्ली, 11 मार्च। पश्चिम एशिया में गहराते संकट और ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव के बीच, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। आपूर्ति बाधित होने की बढ़ती आशंकाओं के मद्देनजर, आईईए के सभी 32 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से अपने आपातकालीन भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का फैसला किया है।

■ एजेंसी के सभी 32 सदस्य देशों ने ईरान वॉर के मद्देनज़र सर्वसम्मति से यह फैसला किया

यह ऐतिहासिक फैसला आईईए के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कदम है। इससे पहले 2022 में, जब रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण स्तर का आक्रमण किया था, तब एजेंसी के सदस्य देशों ने बाजार में 18.2 करोड़ बैरल तेल उतारा था। वर्तमान फैसला पिछले रिकॉर्ड के दोगुने से भी अधिक है।

'बुकिंग के ढाई दिन में ही मिलेगा गैस सिलेंडर'

केन्द्रीय पैट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने यह घोषणा की

नई दिल्ली, 11 मार्च। केन्द्र सरकार का कहना है कि देश में कच्चे तेल का आयात बाधित नहीं है और विविध स्त्रोतों से आवश्यकता के अनुरुप आयात सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं, घरेलू गैस की सप्लाई कुछ हद तक बाधित होने के कारण सरकार प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई सुनिश्चित कर रही है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में बुकिंग के ढाई दिन के अंदर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। कालाबाजारी रोकने के लिए क्यूआर कोड के जरिए बुकिंग की व्यवस्था की गई है।

पश्चिम एशिया में युद्ध के हालात के बीच होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही बाधित है। इस कारण इस मार्ग से विभिन्न देशों को होने वाला आयात प्रभावित है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसे देखते हुए, आज सरकार ने स्थिति स्पष्ट करने के लिए राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में विभिन्न मंत्रालयों की ओर से संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि एलपीजी बुकिंग को लेकर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।

■ उन्होंने बताया कालाबाजारी रोकने के लिए क्यू आर कोड से सिलेंडर बुकिंग की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान में प्राकृतिक गैस की दैनिक खपत लगभग 189 मिलियन मीट्रिक मानक घनमीटर प्रतिदिन है। इसमें से लगभग 97.5 मिलियन मीट्रिक मानक घनमीटर प्रतिदिन का उत्पादन घरेलू स्तर पर होता है और शेष आयात किया जाता है। आयात से लगभग 47.4 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर की आपूर्ति अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण प्रभावित हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छामृत्यु की इजाज़त दी

12 वर्षों से कोमा में चल रहे 32 वर्षीय युवक के जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी

नई दिल्ली, 11 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छामृत्यु की इजाजत दी है। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 12 वर्षों से कोमा में चल रहे 32 वर्षीय व्यक्ति के जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी है, जिससे उसका जीवन प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाएगा।

हालांकि कोर्ट ने एम्स दिल्ली को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चत करे कि जीवन रक्षक उपकरण और प्रणाली एक सुनियोजित योजना के तहत हटाई जाए, ताकि व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, उसे कोई कष्ट या पीड़ा न हो। कोर्ट ने कहा कि उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं, यह सिर्फ दुख को बढ़ाएगा।

■ वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कॉमन कॉज के मामले में इच्छा मृत्यु को मान्यता देने का फैसला किया था, पर अब तक कभी भी ऐसा आदेश नहीं दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर भारत में परोक्ष इच्छामृत्यु (पैसिव यूथनेशिया) का यह पहला मामला है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2018 में कॉमन कॉज के मामले में परोक्ष इच्छामृत्यु को मान्यता का फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि कोमा जैसी स्थिति में पहुंचे रोगी की जीवन रक्षक प्रणाली हटाने के संबंध में विशेषज्ञ राय के लिए एक प्राथमिक और एक सैकेंड्री चिकित्सा बोर्ड का गठन करना होगा और उसकी राय पर ही फैसले में तय दिशा-निर्देशों के मुताबिक परोक्ष इच्छामृत्यु की इजाजत हो सकती है।

इस फैसले के बावजूद, आजतक किसी भी मामले में इससे पहले कभी किसी को इसकी इजाजत नहीं मिली थी। शीर्ष अदालत ने बुधवार को दिए फैसले में केन्द्र सरकार से परोक्ष इच्छामृत्यु पर व्यापक कानून लाने पर विचार करने को भी कहा है। परोक्ष इच्छा मृत्यु किसी व्यक्ति की जीवन रक्षक प्रणाली हटाने और आवश्यक उपचार बंद करके उसे प्राकृतिक रूप से मरने देने की प्रक्रिया को कहते हैं। बुधवार को न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने परोक्ष इच्छामृत्यु की इजाजत मांगने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए इच्छामृत्यु की इजाजत देने का यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जीवन रक्षक उपकरण हटाने की इजाजत देते हुए कहा, उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं, यह सिर्फ दुख को बढ़ाएगा। यह मामला गाजियाबाद के हरीश राणा का है जो पंजाब विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग के छात्र थे और 2013 में अपने पेइंग गेस्ट आवास की चौथी मंजिल गिर गए थे।

कांग्रेस प्रत्याशी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लगाया था कि उपचुनाव के दौरान नामांकन पत्र के साथ जमा किए गए हलफनामे में, मल्होत्रा ने अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी। हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि मल्होत्रा ने अपने नामांकन के साथ दिए हलफनामे में चार आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी नहीं दी थी। मामले में दलील दे रहे अधिवक्ता एम पी एस रघुवंशी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट कई बार यह निर्देश दे चुका है कि नामांकन भरते समय उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। अदालत ने पाया कि इस नियम का पालन नहीं किया गया और इसलिए मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया गया।

स्पीकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सामान्य घटना नहीं है। करीब चार दशक बाद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है।

घरेलू एलपीजी की आपूर्ति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

(एल.एन.जी.) और पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) की उभरती कमी यह दिखाती है कि भारत की ऊर्जा व्यवस्था आपस में कितनी जुड़ी हुई है। एलएनजी की कमी का असर पहले ही उर्वरक कारखानों पर पड़ रहा है, जिससे कुछ इकाइयों को उत्पादन कम करना पड़ रहा है और आयात पर निर्भरता बढ़ रही है। इसका असर केवल खाद्य सुरक्षा पर ही नहीं, बल्कि उर्वरक सब्सिडी पर भी पड़ेगा, जो पहले से ही सरकार के बजट की सबसे बड़ी मदों में से एक है। गैस आपूर्ति में शुरू हुई बाधा जल्दी ही कृषि, महंगाई और सरकारी वित्त पर असर डाल सकती है।

तीसरा, घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के सरकार के फैसले का असर कमर्शियल उपभोक्ताओं, जैसे रेस्तरां, होटल और छोटे खाद्य कारोबार, पर पड़ना तय है। घरेलू खपत की रक्षा करना एक तार्किक नीति है, लेकिन अगर कमर्शियल एलपीजी की कमी लंबे समय तक रहती है तो इससे खासकर छोटे प्रतिष्ठानों को नुकसान हो सकता है, जो बहुत कम मुनाफे पर काम करते हैं। इसलिए नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्राथमिकता अस्थायी रहे और आपूर्ति में लंबे समय का असंतुलन न पैदा करे।

अंत में, यह घटना पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक झटकों के प्रति भारत की लगातार बनी हुई संवेदनशीलता को भी उजागर करती है। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग व्यवस्थाओं में से एक होने और आयात के विविध स्रोत होने के बावजूद देश अभी भी बाहरी ऊर्जा आपूर्ति पर काफी निर्भर है। बार-बार आने वाले संकट, चाहे तेल के झटके हों या गैस की कमी, यह सिखाते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा को केवल तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में देखना होगा। सरकार के तेज हस्तक्षेप से फिलहाल स्थिति को स्थिर करने में मदद मिली है। लेकिन जब वैश्विक ऊर्जा बाजार अनिश्चित बने हुए हैं, तब असली चुनौती केवल मौजूदा संकट को संभालने की नहीं, बल्कि एक अधिक मजबूत और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था बनाने की है।

भारत में गहराया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैं, जो अब तक नहीं देखा गया था, खासतौर से तब से, जब मध्य-पूर्व और यूक्रेन के संघर्ष क्षेत्रों विशेष रूप से क्योंकि मध्य-पूर्व और यूक्रेन के संघर्ष क्षेत्रों में भारत की 147 करोड़ की आबादी को खिलाने की क्षमता को इसी तरह से कमजोर किया गया है। यह रोजगार और आजीविका पर भी असर डालता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर बेहद निर्भर है।

डेटा के अनुसार, युद्ध और होर्मुज़ पर अनौपचारिक नाकाबंदी के कारण भारत को उर्वरक सप्लाई चेन में 20-25 प्रतिशत जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि तेल की तरह, खाड़ी क्षेत्र से, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब और ओमान से, शिपमेंट होर्मुज़ जलडमरूमध्य के माध्यम से ही भेजे जाते हैं कृषि क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, यह कोई मामूली परेशानी नहीं है।

ईरान ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चूंकि इस भ्रष्ट सरकार ने हमारे नेता की हत्या की है, इसलिए हमारा वर्ल्ड कप में भाग लेने का कोई इरादा नहीं है।

ईरान के इस फैसले से फीफा के लिए भी स्थिति जटिल हो गई है। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प के साथ वाइट हाउस में बैठक के बाद सोशल मीडिया पर कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया है कि ईरान की टीम का वर्ल्ड कप में स्वागत किया जाएगा।

विधानसभा चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शक्तिशाली और प्रभावशाली माने जाते हैं। अब तक राहुल गांधी या उनके कार्यालय की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि यह चुप्पी ज्यादा समय तक नहीं चल सकती, खासकर तब जब यह आशंका जताई जा रही है कि यह घोटाला केरल चुनाव को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस वहां लगातार दो हार के बाद फिर से सत्ता में लौटने की उम्मीद कर रही है। भाजपा और वाम दल दोनों ही इन नेताओं के खिलाफ सक्रिय हो गए हैं। यह वित्तीय घोटाला अब केरल, हरियाणा और नई दिल्ली में चर्चा का विषय बन गया है।सूत्रों का कहना है कि इसी नेता से जुड़ा एक और मामला, जो एक महिला से संबंधित बताया जा रहा है, सामने आने वाला है और किसी भी समय बड़ा विवाद बन सकता है। संबंधित महिला भी हरियाणा की बताई जा रही है।

क्या ट्रंप युद्ध खत्म करने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जहाजों की सुरक्षा करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कमी बनी रही। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और इज़रायल के पास ईरान की तुलना में विशाल शक्ति है।

फिर भी, उस शक्ति असंतुलन के बावजूद, ईरान ने संयुक्त सेनाओं और उनके हमलों का मुकाबला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों के विपरीत, ईरानी शासन को ईरानी जनता का भारी समर्थन प्राप्त हुआ है, जबकि ठीक एक महीने पहले तक यह शासन ईरानी लोगों की घृणा का पात्र था।

इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे , कि ईरान का कोई भी नया नेता संयुक्त बलों द्वारा मारा जाएगा, के खिलाफ आईआरजीसी ने नए नेता के रूप में दिवंगत नेता खामनेई के बेटे का नाम लिया है। यह एक उत्तेजक कदम था, जैसे उग्र सांड को लाल लाल कपड़ा दिखाना।

इसके अलावा, ईरान के आक्रमणों के कारण, पश्चिमी एशियाई खाड़ी की क्षेत्रीय शक्तियाँ भी परेशानी महसूस कर रही हैं और युद्ध से बाहर निकलने के तरीकों की तलाश कर रही हैं। ये देश युद्ध के मोर्चे पर हैं, जबकि अमेरिका आठ हजार मील दूर सुरक्षित है।

दूसरी ओर, अपने अहम् को भुलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के तेल के अधिक प्रवाह को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। अमेरिका ने यह घोषित किया कि उसने भारत को रूस का तेल खरीदने की अनुमति दी है, जिसे बाद में भारत ने नकारा।

संकेतों के अनुसार, यूरोपीय देशों को भी रूस का तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, अगर कुछ भी नहीं तो वैश्विक तेल बाजार को शांति देने के लिए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति से भी बात की है।

राष्ट्रपति ट्रम्प के दावों को खारिज करते हुए, भारत ने अपनी संप्रभु अधिकार को दोहराया कि वह तेल और किसी अन्य चीज़ को अपनी समझ और स्वतंत्रता से खरीदेगा, न कि अमेरिका की छूट पर निर्भर होगा।

इस प्रकार संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका ईरान के साथ अपने महंगे युद्ध को समाप्त करने के विकल्प की तलाश में है और ईरान अमेरिकी संपत्तियों और उसके सहयोगियों पर अपने आक्रोशित हमलों को जारी रखने की धमकी दे रहा है।

अमेरिका -इज़रायल ईरान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिया है। इससे पहले तेल की कीमतों में थोड़ी नरमी आने लगी थी, लेकिन अब वे फिर बढ़ने लगी हैं।

डॉनल्ड ट्रंप की दिलासा देने वाली बातों के बावजूद यह पता चला है कि अमेरिका होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर झूठी अफवाहें फैला रहा था। दिन के समय यह दावा किया गया था कि एक सशस्त्र अमेरिकी जहाज पहले ही एक जहाज को स्ट्रेट से सुरक्षित पार करा चुका है, लेकिन बाद में वाइट हाउस ने औपचारिक रूप से इस दावे से इनकार कर दिया।

इससे स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि दावों और खंडनों से साफ हो गया कि अब तक अमेरिका होर्मुज़ को जबरन खुला रखने में सफल नहीं हो पाया है। इसके बाद उसने यह भी दावा किया कि अमेरिकी बलों ने इस पानी में ईरान के 16 बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों को डुबो दिया है। हालांकि यह साफ है कि हमले की तैयारी में ईरान पहले ही स्ट्रेट में भारी मात्रा में सुरंगें बिछा चुका है। पश्चिम एशिया का यह युद्ध अब तेजी से तेल की कीमतों की लड़ाई में बदलता जा रहा है। जहाँ डॉनल्ड ट्रंप और अमेरिकी अधिकारी तेल और गैस की कीमतें कम करने का वादा कर रहे हैं, वहीं वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें ऊँची बनी हुई हैं और तेल खरीदने वाले देशों में डर का माहौल है। जब से युद्ध शुरु हुआ है, तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गई और कल ही यह घटकर 90-91 डॉलर प्रति बैरल तक आई थी। लेकिन बुधवार के दिन फिर से इसमें तेज बढ़ोतरी देखी गई। इस बीच यूरोपीय सरकारें बाजार को शांत करने के लिए अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिज़र्व से तेल जारी करने पर सहमत हो गई हैं।

जी-7 और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने अपने स्ट्रैटोजिक ऑयल रिज़र्व से 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में छोड़ने पर सहमति दी है, जो उनके कुल तेल भंडार का लगभग एक तिहाई हिस्सा है। तथापि, इतने बड़े पैमाने पर तेल जारी करने के वादों के बावजूद बाजार शांत नहीं हुए हैं। गैस की स्थिति तो और भी खराब है, क्योंकि कतर के कुछ सबसे बड़े गैस क्षेत्रों को बंद कर दिया गया है।

तेल बाजार स्ट्रैटोजिक ऑयल रिज़र्व से तेल रिलीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ईरान ने उस संकरे मार्ग को बंद करने का पक्का इरादा कर लिया है, जिससे दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का आवागमन होता है। इससे तेल की कीमतों को स्थिर करने की सभी कोशिशों को बड़ा झटका लग रहा है।

होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ईरान की भाषा और कार्रवाई दोनों ही ज्यादा आक्रामक होती जा रही हैं, जबकि अमेरिकी पक्ष जहाजों को स्ट्रेट से सुरक्षित निकालने के बड़े-बड़े दावे कर रहा है। इन दावों और जवाबी दावों ने अफवाहों को खत्म करने के बजाय डर और भ्रम को और बढ़ा दिया है।

इज़रायल के प्र.मंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ये संभवतः ईरान की सैन्य सफलता को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करने की प्रचार रणनीति का हिस्सा हो सकती हैं।

पिछले कुछ दिनों से, नेतन्याहू सार्वजनिक रूप से नज़र नहीं आए हैं, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। पिछले तीन दिनों से इजरायली प्रधानमंत्री का कोई वीडियो जारी नहीं किया गया और चार दिनों से उनकी कोई तस्वीर भी प्रकाशित नहीं की गई है। संघर्ष के पहले चरणों में, नेतन्याहू से संबंधित कम से कम एक - और अधिकतम तीन - वीडियो प्रतिदिन अपलोड किए जाते थे। पिछले तीन दिनों में, उनके नाम से जो बयान जारी किए गए हैं, वे केवल लिखित संदेश थे। ईरानी रिपोर्ट्स ने यह भी कहा कि 8 मार्च को नेतन्याहू के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि संभावित ड्रोन हमलों का डर था। तसनीम न्यूज एजेंसी ने यह भी संकेत दिया कि उसी समय, दो अमेरिकी प्रतिनिधियों - जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ - की योजनाबद्ध यात्राओं को रद्द कर दिया गया था। ईरानी समाचार एजेंसी द्वारा उठाया गया एक और बिंदु यह था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नेतन्याहू और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच एक फोन कॉल हुई थी। इस बातचीत के बाद, फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय ने बातचीत का केवल लिखित सारांश जारी किया, बिना ऑडियो या वीडियो के। बयान में यह भी नहीं बताया गया कि यह बातचीत किस तिथि को हुई थी। तसनीम न्यूज एजेंसी के अनुसार, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि या खंडन नहीं किया गया है।

इस बीच, ईरान की फार न्यूज़ एजेंसी ने एक सैन्य प्रवक्ता का हवाला देते हुए कहा कि खैबर मिसाइलों ने नेतन्याहू के कार्यालय और इज़राइल के वायु सेना प्रमुख तोमर बार के आवास को निशाना बनाया। हालांकि, इजरायली रिपोर्टों में कहा गया कि यरूशलम में कोई पुष्ट मिसाइल हमले नहीं हुए और नेतन्याहू के कार्यालय को कोई नुकसान नहीं हुआ।

संयोग से, रिपोर्ट में उद्धृत सैन्य प्रवक्ता ने पहले दावा किया था कि कुवैत के ऊपर तीन अमेरिकी लड़ाकू विमान गिराए गए थे। बाद में अमेरिकी सरकार ने कहा कि ये विमान कुवैत के अपने एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा दुर्घटनावश हिट हुए थे।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालयः** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालयः** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालयः** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्सः 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908